राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 198

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 26 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

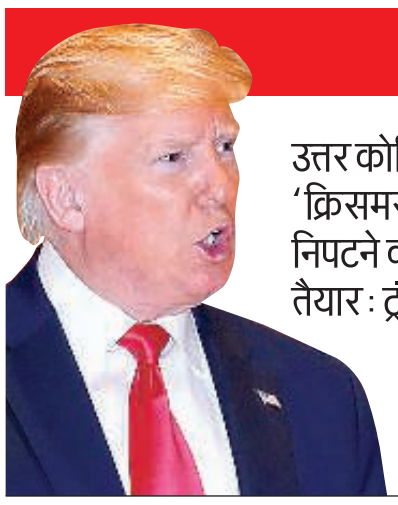

उत्तर कोरिया के 'क्रिसमस गिफ्ट' से निपटने को अमेरिका तैयार : ट्रंप

>> 13

सरोकार

सत्याग्रही की पुकार, हजारों जुबां ने दी आवाज

सोनभद्र : टांगी छोड़ कुदाल उठाओ बंधी नई बनाओ रे, पानी रोको पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ रे... नारे ने तीन दशक में बदले हालात। उप्र के सोनभद्र का 225 वर्ग किमी क्षेत्र आज जलसंकट मुक्त हो गया है। (पेज-6)

जागरण विशेष

शीला के बहाने ओशो को फिर ढूंढ रही दुनिया...

नई दिल्ली : ओशो के आध्यात्मिक साम्राज्य की 'सर्वेसर्वा' रहीं उनकी सबसे करीबी शिष्या आनंद शीला के बहाने ओशो फिर चर्चा में आ गए हैं। शीला के जीवन पर प्रियंका चोपड़ा फिल्म, करण जौहर व शकुन बत्रा नेटफ्लिक्स सीरीज बनाने जा रहे हैं। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

झारखंड में मंत्री बनने को लेकर शुरू हो गई लॉबिंग

रांची : झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में मंत्रालय को लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से लेकर राहुल गांधी के प्रिय लोगों तक विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है और इसके साथ ही नए विधायकों के लिए सक्रिय लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, टूटा रिकॉर्ड

नई दिल्ली : बर्फीली हवाओं के कारण समूचा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। 30 दिसंबर से तापमान में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

कॉरपोरेट सेक्टर के सामने घरेलू फंड का टोटा

नई दिल्ली : कॉरपोरेट सेक्टर के आंकड़े बता रहे हैं कि घरेलू स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने की गति कम हुई है। यह भी नहीं जा कहा जा सकता है कि कंपनियों की तरफ से ही मांग कम हो गई है, क्योंकि यही कॉरपोरेट सेक्टर विदेश से जमकर कर्ज ले रहा है या फंड जुटा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

भारत से पोलियो मार्कर आयात करेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने अपने कदम वापस लेते हुए भारत से पोलियो मार्कर आयात (खरीदने) करने का फैसला किया है। मार्कर से उन बच्चों की अंगुलियों पर निशान लगाए जाते हैं जिन्हें पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। यह प्रक्रिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाक ने भारत के साथ कारोबार रोक दिया था।

सख्ती ▶ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर पहली बड़ी कार्रवाई

उप्र में उपद्रवियों को भेजा वसूली का नोटिस

रामपुर में हिंसा करने वाले 28 आरोपितों को 17 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति करने को कहा

जेएनएन, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आड़ में हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। न केवल उपद्रवियों की शिनाख्त और धरपकड़ में तेजी आई है, बल्कि नुकसान के आकलन के बाद वसूली की दिशा में भी पुलिस-प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई रामपुर में सामने आई है, जहां बवाल में हुए 17 लाख के नुकसान की भरपाई के लिए 28 आरोपितों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है।

रामपुर में हुई हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को 17 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। इसकी वसूली के लिए प्रशासन ने उन 28 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जो जेल भेजे जा चुके हैं। जेल में ही इन्हें नोटिस तामील कराई जाएगी। नोटिस में आरोपितों से अपनी सफाई में साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया है। यदि इनका जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो प्रशासन इनसे वसूली करेगा। धनराशि जमा न करने पर इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और फिर नीलाम की जाएगी।

इसके अलावा पुलिस ने शहर में जगह-जगह उपद्रवियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। इसमें बवाल करते लोगों के फोटो हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डा. अजय पाल शर्मा ने बताया कि वीडियो फुटेज से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस धरपकड़ के लिए दबिश भी दे रही है।

लखनऊ में अब तक 110 लोगों को नोटिस : लखनऊ को हिंसा की आग में झोंकने वाले 110 लोगों को अब तक नोटिस जारी किया गया है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो क्षेत्रवार हुए नुकसान का मूल्यांकन कर रही हैं। हिंसा और उपद्रव में यहां करीब पांच करोड़ की निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। अभी तक तक केवल मदेयगंज में ही तहसील प्रशासन ने करीब 27 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया है।

संभल में 26 लोगों को नोटिस, अमरोहा व गोरखपुर में भी कड़ाई : संभल में भी नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि अभी तक हिंसा और आगजनी के मामले में चिह्नित किए गए 26 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस उनके घरों पर चस्पा किए जा रहे हैं। 43 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरोहा में 28 उपद्रवियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुए हैं। गोरखपुर में पत्थरबाजी के मुकदमे में फरार चल रहे 33 नामजद आरोपितों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। गुरुवार तक बयान दर्ज न कराने पर कुर्की होगी। वहीं बिजनौर के नहटौर में हिंसा में चार दिन बाद थानेदार नप गए हैं। मुकदमों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित की गई है। पुलिस ने जिलेभर में सौ से अधिक बवालियों को चिन्हित किया है। यहां अब तक 146 गिरफ्तारी हुई है।

- सूबे में उपद्रवियों को चिह्नित कर उनके पोस्टर सार्वजनिक कर रही है पुलिस
- उपद्रवियों को न रोक पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गिरी गाज

लखनऊ में फ्लैग मार्च करते पुलिसकर्मी। फाइल फोटो

आपराधिक रिकॉर्ड वाले पत्थरबाजों पर होगी रासुका की कार्रवाई

पत्थरबाजी और उपद्रव करने वालों की पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड तलाश रही है। जिन पत्थरबाजों का आपराधिक रिकार्ड मिलेगा, उनके विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई होगी। शासन ने इस बाबत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर चिह्नित किए जा चुके पत्थरबाजों का आपराधिक रिकार्ड निकलवाकर उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उप्र को जलाने वाले खुद से पूछें क्या-उनका रास्ता सही था : मोदी

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीएए के खिलाफ हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले अपने घरों में बैठकर खुद से सवाल करें कि क्या उनका रास्ता सही था? क्या उनकी प्रवृत्ति सही थी? जिन सरकारी संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, क्या वे उनके बच्चों के काम आने वाली नहीं थीं? हिंसा में जो लोग मारे गए और पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके परिवारीजन के बारे में भी सोचें। (पेज-3)

पोस्टर चस्पा होते ही कटवाने लगे स्टाइलिश दाढ़ी, छोटे कराए बाल पेज>>5

यमुना प्राधिकरण के जमीन घोटाले की जांच करेगी सीबीआइ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ के जमीन घोटाले की जांच अब सीबीआइ करेगी। सीबीआइ ने सेवानिवृत्त आइएएस व प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता समेत 21 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कई आरोपित जेल में बंद हैं। मामले की जांच अब तक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कर रही थी। बीटा दो कोतवाली में बीते साल दर्ज हुई पहली एफआइआर को ही सीबीआइ ने टेकओवर किया है।

यमुना प्राधिकरण में 2013-14 में हुए भूमि घोटाले के संबंध में तीन जून, 2018 को ग्रेटर नोएडा के बीटा दो कोतवाली में प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ सेवानिवृत्त आइएएस पीसी गुप्ता सहित 21 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित पीसी गुप्ता को 22 जून, 2018 को मप्र के दतिया से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मास्टर प्लान से बाहर जाकर प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदी गई थी। बाद में उसी जमीन का मुआवजा अपने रिश्तेदारों को बांट दिया गया था।

सेवानिवृत्त पीसीएस भी हुए गिरफ्तार : घोटाले में शामिल प्राधिकरण के तत्कालीन एसीईओ व सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी सतीश कुमार को एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था। वह भी जेल में बंद हैं।

अटल भूजल योजना लांच, 15 करोड़ घरों को नल से जल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों के 15 करोड़ घरों में नल से जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जल से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में कुल साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल से जुड़े बड़े फैसलों का एलान करते हुए कहा, 'जल संकट से देश का विकास प्रभावित होता है।' उन्होंने किसानों और महिलाओं से पानी की बर्बादी रोकने की अपील करते हुए कहा, 'तकनीक के जरिये कृषि समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।' मोदी बुधवार को यहां अटल जयंती पर आयोजित एक समारोह में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक के 78 जिलों में चलेगी, जिसका लाभ वहां के 8350 गांवों को मिलेगा।

मोदी ने कहा, इस योजना पर 6000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें तीन हजार करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी, तीन हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से प्राप्त होंगे। योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल स्तर ऊपर उठाने का है, जिन इलाकों में यह बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। इससे जहां कृषि क्षेत्र का भला होगा, वहीं लोगों को अच्छे पेयजल की आपूर्ति में मदद मिलेगी।

अटल भूजल योजना की सफलता के बारे में मोदी ने कहा, इसका सारा दारोमदार पंचायतों पर है। इनके लिए स्थानीय स्तर पर ही जल समितियां बनेंगी। उन्होंने स्टार्टअप के लोगों से उम्मीद जताई कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जिससे कम पानी में ज्यादा काम हो सके। कहा, धान व गन्ने की खेती में बहुत पानी लगता है। इसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है। इसके लिए हम पांच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पानी से जुड़े कई विभागों को एक साथ जोड़कर एक जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया है। विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं को एक साथ किया है। उपलब्ध जल के साथ संचयन व वितरण पर जोर है। पानी के कम उपयोग से अधिक काम और गंदे पानी की रिसाइकीलिंग को प्रमुखता दी गई है। जल के प्रति जागरूकता और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है।' उन्होंने कहा, एक तरफ 'जल जीवन मिशन' है, जो हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ 'अटल जल योजना' है, जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे है। इसीलिए जल से संबंधित योजनाओं को पूरा करने पर केंद्र व राज्य सरकारों को मिलाकर कुल साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। मोदी ने कहा, गत 70 वर्षों में सिर्फ तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पाइप से पानी की आपूर्ति हो पाई है। अगले पांच सालों में 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति की जाएगी।

जल है तो कल है

- उप्र, हरियाणा समेत सात राज्यों में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने पर होगा काम
- पानी की विभिन्न योजनाओं पर खर्च होंगे साढ़े तीन लाख करोड़
- पीएम की किसानों और महिलाओं से पानी की बर्बादी रोकने की अपील

नई दिल्ली में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना लांच की। प्रेट्र

अयोध्या पर हमले की फिराक में जैश, अलर्ट जारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में जगह-जगह हमले कराने की साजिश रची है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से हमले के खतरे का अलर्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या में चार माह में गगनचुंबी राम मंदिर बनाने की घोषणा करने के बाद आतंकी संगठन से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'टेलीग्राम' पर अजहर मसूद ने वीडियो संदेश जारी कर अपने गुर्गों को अयोध्या में आतंकी हमले करने को कहा है। इस खुफिया जानकारी से पहले ही देश की सुरक्षा एजेंसियां इस बात से भी चिंतित हैं कि एक माह पहले ही सात पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुस चुके हैं। माना जाता है कि यह आतंकी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गोरखपुर और अयोध्या में छिपे हुए हैं और पुलिस अब तक इन्हें तलाश नहीं कर पाई है। जैश के इन सात दुर्दांत आतंकियों में से पांच की पहचान की जा चुकी है। इनके नाम मुहम्मद याकूब, अबू हमजा, मुहम्मद शाहबाज, निसार अहमद और मुहम्मद कौमी चौधरी है।

- खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद राम की नगरी में सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था
- एक महीने पहले ही सात आतंकी नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं घुसपैठ

प्रतीकात्मक फोटो

पीएम के दौरे में भी रहा अलर्ट : आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने उन सातों आतंकियों की तलाश युद्धस्तर पर जारी रखी है, लेकिन इन आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसके चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में बुधवार के दौरे को भी अति सतर्कता की श्रेणी में रखा गया।

एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी : सूत्रों का कहना है कि समूची नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। पाकिस्तान लगातार नेपाल से लगी सीमा के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। इन आतंकियों के पास भारी तादाद में हथियार भी हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अयोध्या में किन-किन स्थानों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। ध्यान रहे कि वर्ष 2005 में भी अयोध्या में आत्मघाती आतंकी हमला हो चुका है।

रामनगरी में बढ़ी निगरानी

रामनगरी अयोध्या में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। वैसे, अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही रामनगरी सहित संपूर्ण जिले में पुलिस की निगरानी बढ़ी हुई है। शहर में 35 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिले की सीमा पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि अधिगृहीत मंदिर परिसर की सुरक्षा पहले से ही चाक-चौबंद है। आतंकी हमले की आशंका के इनपुट के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। एक आइएसआइ एजेंट की गिरफ्तारी भी शहर के खवासपुरा इलाके से हो चुकी है।

बंगाल के मंत्री को बांग्लादेश ने नहीं दिया वीजा

कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर मचे सियासी घसासान के बीच बांग्लादेश ने बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी को वीजा देने से मना कर दिया है। चौधरी जमीयत-ए- उलेमा हिंद के बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। सिद्दीकुल्लाह ने कहा, मैंने 10 दिन पहले ही वीजा के लिए आवेदन किया था। मेरा हवाई टिकट भी बुक हो गया था, लेकिन बांग्लादेश हाई कमीशन से वीजा देने से मना कर दिया गया। (पेज-5)

उड़ी में सेनाकर्मी शहीद, महिला की भी मौत, पाक में भारी तबाही

श्रीनगर : पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को उड़ी सेक्टर में अग्रिम सैन्य व नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी की, जिसमें सेना के नायब सूबेदार शहीद हो गए और एक महिला की मौत हो गई। वहीं, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की एक निगरानी चौकी के पूरी तरह तबाह होने के साथ उसके जवान के मारे जाने और पांच से छह सैनिकों के घायल होने की सूचना है। (पेज-7)

विधायकों को सलाहकार बनाने पर राज्यपाल ने अमरिंदर से पूछा, वेतन-भत्ता क्या होगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब में छह विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के लिए पारित विधेयक राजभवन की आंखों में खटक रहा है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने इस पर कई सवाल खड़े करके कैप्टन सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर कैप्टन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) संशोधन विधेयक-2019 पास करवा लिया। इसमें विधायकों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया। पहले इसके लिए अध्यादेश लाया गया था। इसमें कुशलदीप सिंह ढिल्लों, कुलजीत नागरा, तरसेम सिंह डीसी, इंद्रबीर सिंह बुलारिया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग व संगत सिंह गिलजियां को मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। इसी मामले पर राज्यपाल ने सरकार से 13 सवाल पूछे हैं।

कैप्टन बोले, विधेयक वापस नहीं किया, स्पष्टीकरण मांगा है: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल ने विधेयक वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने केवल कुछ चीजों पर स्पष्टीकरण मांगा है और जल्द ही यह राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारियों को राज्यपाल की ओर से पूछे गए सवालों का जल्द से जल्द जवाब भेजने को कहा गया है। सरकार ने छह में से पांच विधायकों कुशलदीप ढिल्लों, संगत सिंह गिलजियां, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कुलजीत नागरा और इंद्रबीर सिंह बुलारिया को कैबिनेट रैंक व तरसेम सिंह डीसी को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है।

क्या-क्या पूछा राज्यपाल ने

- क्या सलाहकारों के पद सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन बनाए गए हैं?
- सुविधाएं, पात्रता, वेतन और भत्ते क्या हैं?
- इन्हें सरकारी फाइलें देखने का हक है?
- क्या रूल्स ऑफ बिजनेस में इनके काम को शामिल किया गया है?
- क्या इन पदों के लिए सरकार ने कोई योग्यता तय की है?
- कितने पदों को सृजित किया गया है, इनकी सीमा क्या है?
- इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? यह किस प्रकार की सलाह सीएम को देंगे?
- सलाह का कानूनी स्टेटस क्या रहेगा?
- क्या हाउस की दिनचर्या के प्रति उनकी जवाबदेही होगी?
- इनकी नियुक्तियों को अदालत में दी गई चुनौती का स्टेटस क्या है?

बदलेगी तस्वीर

केंद्र सरकार गांवों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, इसके लिए भारतनेट को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है

भारतनेट से जुड़े सभी गांवों को मार्च तक मिलेगी मुफ्त वाई-फाई सेवा

नितिन प्रधान, रेवाड़ी

सरकार भारतनेट से जुड़े देश के सभी गांवों में अगले साल मार्च तक मुफ्त वाई-फाई सेवा देगी। केंद्रीय संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे देश में भारतनेट सेवा को प्रोत्साहन मिलेगा और इसका विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 1.30 लाख ग्राम पंचायतें भारतनेट से जुड़ चुकी हैं। सरकार का इरादा देश की ढाई लाख पंचायतों को भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का है। फिलहाल देश के 48,000 गांवों में भारतनेट के जरिये वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है।

बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गुरावड़ा गांव को डिजिटल गांव घोषित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिये सरकार हर गांव में बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। सरकार देश में एक लाख डिजिटल गांव बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। हरियाणा के इस गांव में प्रदेश सरकार की सभी सेवाएं सीएससी के जरिये उपलब्ध हैं। इनमें बैंकिंग से लेकर पेंशन तक के लिए लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता। प्रसाद ने कहा कि सीएससी ने शहरी सेवाओं को गांव में ला दिया है। उन्होंने गुरावड़ा में सीएससी चला रही महिला सोनू बाला को सम्मानित भी किया।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस सुशासन दिवस पर इस गांव को डिजिटल गांव में बदलकर उन्हें खुशी हो रही है। इसकी वजह यह है कि स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन को उत्तरदायी बनाना होगा। डिजीटल सशक्तता से यह काम काफी सरल होगा। एक क्लिक पर आम नागरिक कोई भी सरकारी सेवा हासिल कर पाएगा। प्रसाद ने कहा इस दिशा में सीएससी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में डिजिटल सेवाएं दे रहे सीएससी की संख्या पिछले पांच साल में 60 हजार से बढ़कर 3.6 लाख हो गई है।

कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी ने कहा कि डिजिटल गांव की घोषणा 2015-16 के बजट में की गई थी। हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच गांवों को डिजीटल बनाया था। उनकी सफलता को देखते हुए सरकार ने हमें देश के हर गांव को डिजिटल बनाने का दायित्व दिया है। इसके माध्यम से लोगों को उनके गांव में बैंकिंग सेवा, टेलीमेडिसन, टेलीएजुकेशन सहित सैकड़ों सेवाएं दी जाती हैं। लोगों को डिजीटल साक्षर बनाने का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा यहां एलईडी बल्ब, सैनेटरी नैपकिन, पेपर बैग बनाने का कार्य भी किया जाता है। जिससे डिजिटल गांव के प्रशासनिक खर्च पूरे किए जा सकें।

- केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का एलान
- भारतनेट से जुड़ चुकी हैं 1.30 लाख ग्राम पंचायतें
- अभी 48,000 गांवों में उपलब्ध है वाई-फाई सुविधा

हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार को गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित करने के मौके पर मीडिया से मुखातिब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। जागरण

दुष्यंत चौटाला की जजपा में बगावत गौतम ने छोड़ा उपाध्यक्ष का पद

जागरण संवाददाता, हिसार

- बोले, 11 महकमे लेकर बैठा है दुष्यंत, पार्टी में हैं और भी अच्छे विधायक

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) में बगावत शुरू हो गई है। नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं, दुष्यंत ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इस मामले को सुलझा लेंगे।

रामकुमार गौतम ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, दुष्यंत की पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है। जाटों का इतना बड़ा वोट मुझे मिला है। हम नौ विधायकों की मदद से ही दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बना है। '11 महकमे लेकर खुद बैठा है। अरे भलेमानस और भी अच्छे विधायक हैं पार्टी में।' उन्होंने कहा, अभी सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, जिस दिन विधायक का पद छोड़ूंगा उस दिन पार्टी छोड़ूंगा। गौतम ने कहा, लोकसभा चुनाव में उचाना विधानसभा क्षेत्र में बृजेंद्र सिंह से दुष्यंत की साढ़े 9 हजार वोटों से हार हुई थी। हमारे सहयोग से उन्होंने बृजेंद्र की मां को हराया है। उन्होंने कहा, मैं जजपा के संस्थापकों में हूं। पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि उसे छोड़ने के बारे में सोचूं। गौतम ने कहा, दुष्यंत जाट बिरादरी में अपने से बड़ा नेता किसी को देखना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा, मुझे मंत्री न बनाए जाने का नहीं, बल्कि इस बात का दुख है कि इन लोगों ने गुरुग्राम के एक मामले में समझौता कर लिया। जब यही करना था तो क्यों इतने लोग मारे, चुनाव से पहले समझौता कर लेते। दुष्यंत की लाइन पिता और दादा वाली ही है। मेरा बस थोड़े ही है, इनकी सोच पर। अगर मुझे मंत्री बनाते तो बड़ी उड़ान भरते। क्या है- अब तो खेल खत्म, पैसा हजम।